

# इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 03 APRIL TO 09 APRIL 2024

■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 28 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside  
News

जितना खाना दुनिया  
एक दिन में फेंक देती है,  
उससे भर सकता है 100  
करोड़ लोगों का पेट

Page 2



क्या 1 अप्रैल से  
टैक्स रिजिम में हो गया  
है बदलाव? वित्त  
मंत्रालय ने दी ये  
जानकारी

Page 3



भारत का डिफेंस  
एक्सपोर्ट 21 हजार करोड़  
रुपए के आंकड़े को पार,  
जानिए क्या-क्या  
एक्सपोर्ट कर रहा भारत

Page 5



editoria!

रक्षा निर्यात में  
बड़ी वृद्धि

वित्त वर्ष 2023-24 में देश का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जो 2022-23 की तुलना में 32.5 प्रतिशत अधिक है। यदि इस भारी बढ़ोतरी की तुलना वित्त वर्ष 2013-14 से की जाए, तो निर्यात में बीते एक दशक में 31 गुना वृद्धि हुई है। साल 2004-05 और 2013-14 तथा 2014-15 और 2023-24 की वृद्धि की तुलना करें, तो निर्यात 21 गुना बढ़ा है। 2004-05 और 2013-14 के बीच 4,312 करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात हुआ था, जबकि 2014-15 से 2023-24 की अवधि में यह आंकड़ा 88,319 करोड़ रुपये जा पहुंचा। इन आंकड़ों से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तीव्र विकास का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है.. हालिया वर्षों में रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इनमें सबसे प्रमुख है रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी और विदेशी निवेश की अनुमति। इससे निवेश के साथ-साथ तकनीक हासिल करने की सुविधा भी बढ़ी तथा रोजगार के नये अवसरों का सृजन भी हुआ। तकनीक और संसाधन बढ़ने से शोध एवं अनुसंधान में भी प्रगति आयी है। नीतिगत सुधारों की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निर्यात में 60 प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्र है और 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही इस उपलब्धि को देश की बढ़ती क्षमता की अभिव्यक्ति बताया है। उत्पादन और निर्यात बढ़ने की दूसरी मुख्य वजह यह है कि सरकार अपनी रक्षा जरूरतों के लिए देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने बहुत सी चीजों की एक सूची बनायी है, जिनकी खरीद देश में ही हो सकती है यानी उनका आयात नहीं किया जा सकता है। यह सूची समय-समय पर संशोधित होती है और इसमें नये उत्पादों को जोड़ा जाता है। इस निर्णय का दूसरा सकारात्मक पहलू यह है कि देश में ही खरीद कर हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत भी कर रहे हैं तथा आयात पर हमारी निर्भरता भी घट रही है। नीतिगत सुधारों और सरकार की खरीद से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। इन प्रयासों से विभिन्न देशों में भारतीय रक्षा उत्पादों के प्रति भरोसा बढ़ा है और वे भारत से अपना आयात बढ़ा रहे हैं। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने में डिजिटल व्यवस्था से भी मदद मिली है। इससे समूची प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हुई है। रक्षा निर्यात आर्थिक विषय होने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने के साथ-साथ रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे हमारी रक्षा क्षमता को मजबूती तो मिलती ही है, साथ में आयातक देशों के साथ सामरिक संबंध भी बेहतर होते हैं।

## देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की ग्रोथ बढ़ी

फरवरी में 6.7 प्रतिशत पर पहुंची

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की ग्रोथ में इजाफा हुआ है। फरवरी में ग्रोथ 6.7 फीसदी रही। बुनियादी उद्योगों की यह वृद्धि दर इस साल जनवरी के मुकाबले ज्यादा है। जनवरी में ग्रोथ 4.1 फीसदी थी। आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। बीते वर्ष फरवरी में यह 7.4 फीसदी थी। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। सरकार ने कहा, 'फरवरी 2024 में कोयला, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, स्टील, कच्चे तेल, बिजली और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज की गई।'

किस सेक्टर का कैसा हाल?

कोयला सेक्टर में 11.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 9 फीसदी थी। इसी तरह कच्चे तेल क्षेत्र में सालाना आधार पर 4.9 फीसदी की गिरावट के मुकाबले



7.9 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। इस्पात और बिजली क्षेत्र की वृद्धि दर सालाना 12.4 और 8.2 फीसदी से घटकर 8.4 फीसदी और 6.3 फीसदी हो गई। हालांकि, फरवरी 2024 में सीमेंट में 10.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जो फरवरी 2023 में 7.4 फीसदी थी। कुल मिलाकर इन क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि

दर चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-फरवरी में घटकर 7.7 फीसदी रही, जो बीते वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल-फरवरी में 8.2 फीसदी थी।

आईआईपी में कोर सेक्टर की कितनी हिस्सेदारी?

प्राकृतिक गैस में ग्रोथ फरवरी

2024 में 11.3 फीसदी रही। फरवरी 2023 में यह 3.1 थी। रिफाइनरी उत्पादों में पिछले साल के 3.3 फीसदी से घटकर पिछले महीने में 2.6 फीसदी रह गई। देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में आठ प्रमुख क्षेत्रों का योगदान 40.27 फीसदी है।

## मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की ऊंची उड़ान, ग्रोथ 16 साल के उच्चतम स्तर पर

नई दिल्ली। एजेंसी

प्रोडक्शन और नए ऑर्डर में मजबूत बढ़ोतरी के दम पर मार्च में भारत के मैनुफैक्चरिंग सेक्टर क्षेत्र की बढ़ोतरी 16 साल के हाई लेवल पर पहुंच गई। 'HSBC इंडिया मैनुफैक्चरिंग पेंचेंजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स' (PMI) मार्च में बढ़कर 59.1 पर पहुंच गया जो फरवरी में 56.9 था। पीएमआई के तहत 50 से ऊपर इंडेक्स होने का मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज में विस्तार है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दिखाता है। HSBC की अर्थशास्त्री इनेस लैम ने कहा कि भारत का मार्च मैनुफैक्चरिंग पीएमआई 2008 के बाद से अपने हाई लेवल पर पहुंच गया। मैनुफैक्चरिंग कंपनियों में मजबूत उत्पादन और नए ऑर्डर से नियुक्तियां बढ़ीं। उत्पादन मार्च में लगातार 33वें महीने बढ़ा। अक्टूबर 2020 के बाद से यह सर्वाधिक बढ़ोतरी है। एचएसबीसी इंडिया मैनुफैक्चरिंग पीएमआई

को एसएंडपी ग्लोबल ने करीब 400 कंपनियों के एक समूह में भेजे गए सवाल के जवाबों के आधार पर तैयार किया है।

क्यों आई तेजी

डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट बाजारों से नए काम का इनफ्लो मजबूत हुआ। सर्वे के मुताबिक मई 2022 के बाद से नए एक्सपोर्ट ऑर्डर सबसे तेज गति से बढ़े हैं। कंपनियों ने बिक्री में अपेक्षित सुधार से पहले स्टॉक बनाने की मांग की थी। भारत में निर्माताओं ने मार्च में अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखा। सर्वे में कहा गया है कि रोजगार सृजन की गति हल्की थी, लेकिन सितंबर 2023 के बाद से सबसे अच्छी है। कीमतों में मामूली गिरावट रहने के बावजूद लागत दबाव पांच महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर था। कंपनियों ने बताया कि उन्होंने कपास, लोहा, मशीनी उपकरण, प्लास्टिक और स्टील के लिए अधिक भुगतान किया है।

Zomato को मिला  
भारी-भरकम GST  
नोटिस, लगा करोड़ों  
रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। एजेंसी

फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो को तागड़ा झटका लगा है। कंपनी को भारी भरकम जीएसटी का नोटिस मिला है। कंपनी को यह नोटिस कर्नाटक में कमर्शियल टैक्स (ऑडिट) के असिस्टेंट कमिश्नर से मिला है। ऑनलाइन ऑर्डर देकर खाना मंगाने की सुविधा देने वाले मंच जोमैटो को कर अधिकारियों से 23.26 करोड़ रुपये की कर मांग का नोटिस मिला है। इसमें ब्याज और जुर्माना शामिल है। कंपनी ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ उपयुक्त प्राधिकार के समक्ष चुनौती देगी। जोमैटो ने बीएसई को दी सूचना में कहा, 'कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त (ऑडिट), कर्नाटक से 11,27,23,564 करोड़ रुपये की जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) मांग को लेकर नोटिस मिला है।

# जितना खाना दुनिया एक दिन में फेंक देती है, उससे भर सकता है 100 करोड़ लोगों का पेट

## नई दिल्ली। एजेसी

अमूमन लोगों के बीच यह धारणा है कि दावतों में सबसे ज्यादा खाना बर्बाद होता है। लेकिन हाल में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा भोजन दावतों में नहीं बल्कि घरों में बर्बाद हो रहा है। जितना खाना दुनिया एक दिन में फेंक देती है, उससे रोजाना 100 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। आइए समझते हैं कि आखिर इतना खाना बर्बाद क्यों हो रहा है।

अगर आप प्लेट में खाना (Food) छोड़ देते हैं या फिर बचा हुआ खाना फेंक देते हैं तो ये खबर आप के लिए हैं। ये हम नहीं आंकड़ें कह रहे हैं कि जितना खाना दुनिया एक दिन में फेंक देती है, उससे 100 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। इसलिए

जरूरी ये है कि खाना थाली में छोड़ने से पहले या फिर फेंकने से पहले आप एक बार फिर सोच लें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस से ठीक पहले जारी की गई नई रिपोर्ट 'Food Waste Index Report 2024' में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक खाने योग्य करीब 20 फीसदी भोजन कचरे में फेंक दिया जाता है। जबकि 2022 से जुड़े आंकड़ों को देखें तो साल में करीब 105.2 करोड़ टन भोजन बर्बाद हो रहा है, जो हर साल प्रति व्यक्ति औसतन 132 किलोग्राम के बराबर है।

**60 फीसदी भोजन घरों में बर्बाद हो रहा**  
रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर

पर खाद्य पदार्थों (इदद् घूरे) की जो बर्बादी हो रही है उसका अधिकांश यानी 60 फीसदी घरों में बर्बाद (Waste) हो रहा है। यदि घर-परिवार में बर्बाद हो रहे इस भोजन की कुल मात्रा को देखें तो वो करीब 63.1 करोड़ टन है। चिंता जनक बात यह है कि जहां एक तरफ इस भोजन बर्बाद हो रहा है वहीं वैश्विक स्तर पर पांच वर्ष से कम आयु के 15 करोड़ बच्चों का विकास (Development) इसलिए अवरूढ़ हो गया क्योंकि उनके आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है।

**फसल उपज से लेकर बिक्री तक 13 फीसदी भोजन का नुकसान**  
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध

कुल भोजन का करीब 19 फीसदी हिस्सा फुटकर दुकानों, खाद्य सेवाओं और घर-परिवारों में बेकार हो रहा है। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का अनुमान है कि फसल उपज से लेकर बिक्री तक, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में करीब 13 फीसदी भोजन का नुकसान हो रहा है। देखा जाए तो यह वो बर्बादी है जिसे टाला जा सकता है। देखा जाए तो खाद्य उत्पादों की होती बर्बादी आज केवल संपन्न देशों तक ही सीमित नहीं है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भी यह समस्या बढ़ रही है। आंकड़े इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि उच्च-आय, ऊपरी-मध्य आय, और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में घर-परिवारों में होने वाली औसत खाद्य बर्बादी में, सालाना प्रति व्यक्ति केवल



सात किलोग्राम का अन्तर है।

## ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की बर्बादी कम

दूसरी तरफ मध्यम आय वाले देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की बर्बादी कम होती है। इसकी एक वजह वहां बची-खुची खाद्य सामग्री को फिर से इस्तेमाल में लाया जाना हो सकता है, क्योंकि इन खाद्य

उत्पादों को मवेशियों के चारे या खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि इससे निपटने के लिए खाद्य पदार्थों की होती बर्बादी में कमी लाने के प्रयासों को मजबूत करना होगा। शहरों में सड़े हुए खाद्य पदार्थों का खाद के रूप में इस्तेमाल कचरे को कम करने में मददगार हो सकता है।

## पेट्रोल-डीजल ही नहीं, लिथियम ऑयन बैटरी सेल भी बनाएगी IOC

### नई दिल्ली। एजेसी

पेट्रोलियम सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Indian Oil) ने बैटरी मैनुफैक्चरिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आईओसी ने जापानी कंपनी पैनासोनिक एनर्जी (Panasonic Energy) के साथ जॉइंट वेंचर शुरू करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि वह पैनासोनिक एनर्जी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर (JV) के जरिये भारत में लिथियम ऑयन सेलों (lithium-ion cells) की मैनुफैक्चरिंग करेगी।

### स्टोरेज बैटरी की बढ़ रही है मांग

कंपनी की तरफ से यहां जारी एक बयान के मुताबिक क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को देखते हुए आईओसी ने यह जॉइंट वेंचर बनाया है। भारतीय बाजार में दोपहिया वाहनों (Two wheelers) और तीन पहिया (Three wheelers) वाहनों में तो लिथियम बैटरी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए भी बैटरी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए कंपनी ने भारत में सिलिंड्रिकल लिथियम ऑयन सेल की मैनुफैक्चरिंग का फैसला किया है।

## सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं चलेगी USSD कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा, जानिए इसका असर

### नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

15 अप्रैल से देश में छपएउ कोड्स के जरिए कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा बंद हो जाएगी। दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल फोन में \*401# डायल करके कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा समाप्त करने का निर्देश दिया है। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी थी जो अक्सर यात्रा करते हैं या एक से अधिक फोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं।

### क्यों बंद हो रही है सुविधा?

सरकार ने यह फैसला ऑनलाइन और फर्जी कॉल के जरिए हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए लिया है। जालसाज इस सुविधा का नाजायज फायदा उठा रहे थे। वे लोगों को टेलीकॉम प्रोवाइडर बनकर

कॉल करते थे और इ401# डायल करने के लिए कहते थे। जैसे ही कस्टमर इस नंबर को डायल करता था, तो जालसाज उसे किसी अनजान नंबर पर कॉल करने के लिए कहता था। ऐसा करते ही कस्टमर के नंबर पर आने वाला हर फोन, मैसेज या धुइइ उस अनजान नंबर पर फॉरवर्ड हो जाता था।

### क्या हैं विकल्प?

सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वे ग्राहकों को कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा फिर से एक्टिवेट करने के लिए विकल्प प्रदान करें। जिन ग्राहकों ने अभी यूएसएसडी से कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा ली हुई है, उनसे कंपनियों 15 अप्रैल के बाद सर्विस को रिक्टिवेट करने के लिए कहेंगी। इसके लिए ग्राहकों को यूएसएसडी से इतर दूसरे विकल्प

दिए जाएंगे। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा बिना ग्राहक की मंजूरी के एक्टिवेट न हो।

### किन लोगों को होगी दिक्कत?

यूएसएसडी बेड सर्विसेज के तहत ग्राहकों को कई सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें कॉल फॉरवर्डिंग की सुविधा भी शामिल है। यह उन लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होती है जो अक्सर यात्रा करते हैं या एक से अधिक फोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग मीटिंग में होने की वजह से अपनी कॉल किसी दूसरे रिजेंटेंटिव को फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे में अब यूएसएसडी बेड कॉल फॉरवर्ड करने की सुविधा बंद होने से बहुत से लोगों को कुछ समय के लिए दिक्कत हो सकती है।

### यह भी ध्यान रखें:

15 अप्रैल के बाद भी छपएउ का इस्तेमाल मोबाइल रिचार्ज, बैलेंस चेक, और अन्य सुविधाओं के लिए किया जा सकता है।

टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को कॉल फॉरवर्डिंग के लिए ऐप-आधारित या एश-आधारित विकल्प दे सकती हैं।

ग्राहकों को किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर \*401# या अन्य USSD कोड डायल नहीं करना चाहिए।

यह बदलाव मोबाइल यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप छपएउ कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा का उपयोग करते हैं, तो आपको इसके बंद होने के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वैकल्पिक तरीकों के बारे में पता लगाना चाहिए।

## अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बीमा पॉलिसी रखना हो जाएगा जरूरी, जानिए इससे क्या फायदा होगा

### नई दिल्ली। एजेसी

जल्द ही आपके पास एक ऐसा e-Insurance Account (EIA) होगा, जिसमें आपकी तमाम इश्योरेंस पॉलिसी जैसे लाइफ, हेल्थ आदि मैनेज होंगी। यह सिक्वोर ऑनलाइन अकाउंट होगा। इसमें सभी इश्योरेंस पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रहेगी। इससे किसी तरह के कागजी दस्तावेज को संभालने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। पॉलिसी होल्डर को फिजिकल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट खोने, फटने का डर रहता है, लेकिन अब यह जोखिम नहीं होगा। इसके

तहत 1 अप्रैल 2024 से सभी इश्योरेंस पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएंगी। अपने EIA में एक बार विवरण अपडेट करने पर, सभी लिंक की गई पॉलिसियों में यह रिफ्लेक्ट होगा। पॉलिसी होल्डर्स अपनी पॉलिसी विवरण और renewal dates को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। बीमा रेगुलेटर IRDAI ने हाल ही में 1 अप्रैल, 2024 से प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसीहोल्डर इंटरैक्ट रेगुलेशन 2024 पेश किया है। यह रेगुलेशन सभी बीमा पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदलने को अनिवार्य

करता है।

CAMS Repository के CEO विवेक बेंगानी का इस बारे में कहना है कि 'अब सभी पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करना अनिवार्य है, चाहे आवेदन का तरीका कुछ भी हो। यह पहल पॉलिसीधारक के पोर्टफोलियो की सुरक्षा और उसके मैनेजमेंट को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।' उन्होंने बताया कि ज्यादातर प्राइवेट लाइफ इश्योरेंस कंपनियों और नॉन लाइफ इश्योरर ने इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाता (EIA) मैकेनिज्म को स्वीकार कर लिया है, जो

पॉलिसीधारकों को अपनी पॉलिसी होल्डिंग्स को डिजिटल बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है।

### स्कैम संभव नहीं

ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर बढ़ती चिंताओं के जवाब में बेंगानी पॉलिसीधारकों को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि CAMS रिपॉजिटरी द्वारा Policy Genie पॉलिसीहोल्डर्स को EIA प्लेटफॉर्म पर शामिल करने के हमारे प्रयासों का हिस्सा है। हमारा मजबूत सुरक्षा सिस्टम सुनिश्चित करता है हर समय ग्राहक डेटा की सुरक्षा हो।

# टैक्स बचाने के लिए फर्जी HRA प्रूफ दिया है? सरकार की है नजर

नई दिल्ली। एजेंसी

टैक्स बचत के लिए लोग न जाने कितनी तिकड़में करते हैं। कई तो किराये तक में गफलत करते हैं। किराये के मकान पर न रहने के बावजूद वे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करने के लिए फर्जी प्रूफ दे देते हैं। अब इस पर सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किरायेदार न होने के बावजूद एचआरए का गलत दावा करने के लिए पैन के फर्जी इस्तेमाल से जुड़ा खेल पकड़ा है। शुरुआत निष्कर्षों के आधार पर लगभग 8,000-10,000 महत्वपूर्ण मामलों की पहचान की गई है। इनमें कई मामलों में 10 लाख रुपये से अधिक की रकम शामिल है। जांच तब शुरू हुई जब अधिकारियों को एक व्यक्ति के पैन के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये की किराया रसीदें मिलीं। हालांकि, पृथक्करण करने पर उसने इन लेनदेन के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। बाद की जांच से पता चला कि उस व्यक्ति को वाकई किराया नहीं मिला था।

इस खुलासे के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जांच का दायरा

बढ़ाया। इससे उन्हें पता चला कि कुछ लोगों ने अपनी कंपनियों से टैक्स डिडक्शन हासिल करने के मकसद से पैन का दुरुपयोग किया। ऐसे दुरुपयोग की सीमा चिंताजनक हो गई है। इस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां कर्मचारियों ने टैक्स बेनिफिट के लिए आइडेंटिक पैन का इस्तेमाल किया है।

## टैक्स अधिकारियों के रडार पर ऐसे कर्मचारी

टैक्स अधिकारियों ने कहा है कि विभाग सक्रिय रूप से उन कर्मचारियों का पीछा कर रहा है जिन्होंने टैक्स बचाने के मकसद से फर्जी क्लेम फाइल किए हैं। हालांकि, यह तय नहीं कि क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी?

TOI की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मामला पैन के दुरुपयोग का एक और उदाहरण उजागर करता है। स्थिति में जटिलता टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की वर्तमान सीमा से बढ़ गई है, जो केवल 50,000 रुपये से अधिक के मासिक किराये या 6 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक भुगतान पर लागू होती है। नतीजतन, कई कर्मचारियों ने रेंटल इनकम

पर टैक्स से बचने के लिए इस खामी का फायदा उठाया है।

## अब आसान है पकड़ना

एक्सपर्ट कहते हैं कि ज्यादातर वित्तीय लेनदेन पैन से जुड़ गए हैं। ऑटोमेटेड प्रोसेस की नई तकनीक और डेटा एनालिटिक्स के साथ टैक्स अधिकारियों के लिए फर्जी क्लेम को ट्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है। इससे न केवल बाद में टैक्स भुगतान, बल्कि जुर्माने और मुकदमेबाजी का भी सामना करना पड़ सकता है। जहां किराये का भुगतान माता-पिता को किया जाता है। वहां लेनदेन की वास्तविकता को दिखाने के लिए किराये का पेमेंट चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिये किया जाना चाहिए। अपने रिटर्न में पैंट्स को भी रेंटल इनकम की जानकारी देनी चाहिए।

## क्या होता है HRA?

एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस सैलरी का एक हिस्सा होता है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को घर का किराया चुकाने में मदद करने के लिए देता है। यह भत्ता टैक्सबल होता है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत कर्मचारी इस पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

# क्या 1 अप्रैल से टैक्स रिजीम में हो गया है बदलाव? वित्त मंत्रालय ने दी ये जानकारी

नई दिल्ली। एजेंसी

सोशल मीडिया पर नए टैक्स रिजीम को लेकर दी जा रही जानकारी पर अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्टता दी है। टैक्सपेयर्स के लिए ये जानकारी काफी अहम है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टैक्स रिजीम को लेकर गलत जानकारी दिए जाने का मामला सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि आज यानी 1 अप्रैल 2024 से टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर क्लियरिफिकेशन भी दिया है। मंत्रालय के मुताबिक, नए टैक्स रिजीम को वित्त विधेयक 2023 में सेक्शन 115BAC(1A) के अंतर्गत पेश किया गया था। पुराने टैक्स रिजीम पहले से मौजूद है। नए टैक्स रिजीम में वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 से कंपनियों और फर्म के अलावा आम टैक्सपेयर्स के लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के रूप में लागू है। इसमें कई तरह के एजम्पशन और डिडक्शन सैलरी से 50 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन और 15 हजार फैमिली पेंशन के अलावा लागू नहीं है। नए टैक्स रिजीम में टैक्स रेट कम है।



वित्त मंत्रालय ने कही ये बात

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर नए और पुराने टैक्स रिजीम को लेकर जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सोशल मीडिया पर टैक्स रिजीम को लेकर कई तरह की

अफवाहें चल रही हैं। लोग इनपर ध्यान न दें। वित्त मंत्रालय की ओर से क्लियरिफिकेशन दिया गया है। नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। वहीं टैक्स पेयर्स अपने फायदे को देखते हुए पुराना या नया इनमें से कोई भी टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। नए टैक्स रिजीम से बाहर निकलने का ऑप्शन आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।

## नहीं किया गया कोई बदलाव

वित्त मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि 1 अप्रैल 2024 से टैक्स रिजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। लोग सोशल मीडिया पर चल रही गलत जानकारियों पर ध्यान न दें।

टैक्सबल इनकम	टैक्स रेट
0 से 2.5 लाख	0
2.5 लाख से 5 लाख	5%
5 लाख से 10 लाख	20%
10 लाख से ऊपर	30%

न्यू टैक्स रिजीम टैक्सबल इनकम	टैक्स रेट
0 से 3 लाख	0
3 लाख से 6 लाख	5%
6 लाख से 9 लाख	10%
9 लाख से 12 लाख	15%
12 लाख से 15 लाख	20%
15 लाख से ऊपर	20% + 3%

(प्रत्येक अतिरिक्त लाख के लिए)

# 2,000 रुपये के नोट पर अपडेट अब RBI ने किया यह ऐलान

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल 19 मई को चौकाते हुए 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। इस ऐलान के साथ इन्हें सर्कुलेशन से हटाने का फैसला किया गया था। हालांकि, उसने कहा था कि 2,000 रुपये के नोट मान्य बने रहेंगे। इन करंसी नोटों को बदलने या जमा करने की डेडलाइन महीनों पहले खत्म हो चुकी है। यह और बात है कि लोग अभी भी केंद्रीय बैंक के इश्यू ऑफिस में ऐसा कर सकते हैं। आरबीआई ने गुरुवार को इससे जुड़ी एक और घोषणा की है। उसने बताया है कि नोटों को वापस लेने की यह सुविधा अगले सप्ताह एक दिन के लिए बंद रहेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को लोग 2,000 रुपये के नोटों को बदल या जमा नहीं कर पाएंगे।



केंद्रीय बैंक ने कहा, 'खातों के वार्षिक समापन से जुड़े कामों के चलते भारतीय रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में सोमवार 1 अप्रैल, 2024 को 2000 के बैंक नोटों के एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यह सुविधा मंगलवार, 2 अप्रैल, 2024 को फिर से शुरू होगी।'

## आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में सुविधा

आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों 2,000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने या जमा करने की सुविधा अभी भी खुली है। इनमें अहमदाबाद, बंगलुरु,

बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम के ऑफिस शामिल हैं।

## कब तक एक्सचेंज किए जा सकते हैं बैंक नोट?

2000 रुपये के बैंक नोट को जमा या बदलने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर, 2023 थी। हालांकि, बैंक खातों में क्रेडिट के लिए 2,000 रुपये के बैंक नोटों को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जारी करने वाले विभागों (आरबीआई निर्गम कार्यालय) में जमा करने की अनुमति बनी रहेगी। कोई व्यक्ति अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी को इंडिया पोस्ट के जरिये 2,000 रुपये के नोट भेज भी सकता है।



# इंडियन प्लास्ट टाइम्स

व्यापार की बुलंद आवाज

अपनी प्रति आज ही बुक करवाएं



विज्ञापन के लिए संपर्क करें।

## 83052-99999

indianplasttimes@gmail.com

## 5G Speed:

### भारत की लंबी छलांग! रैंकिंग में दिग्गज देश छोटे पीछे

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में करीब एक साल पहले 5G नेटवर्क को रोलआउट किया गया था। उस वक्त मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की रैंकिंग बेहद खराब थी। लेकिन अब एक साल बाद हालात बदल चुके हैं। भारत आज के वक्त में दुनिया के टॉप 15 देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है, जहां सबसे तेज स्पीड 5G नेटवर्क ऑफर किया जा रहा है। भारत में जियो और एटरनेल की ओर से हाई स्पीड 5G नेटवर्क ऑफर किया जा रहा है।

#### अपलोडिंग स्पीड में भारत रहा अब्बल

नेटवर्क टेस्टिंग और एनालिसिस फर्म Ookla की रिपोर्ट की मानें, तो साल 2024 की चौथी तिमाही में भारत की 5G डाउनलोडिंग स्पीड के मामले में 14वां स्थान था। इस दौरान स्पीड करीब 301.86 Mbps थी, जबकि मीडियन अपलोडिंग स्पीड 18.93 mbps रही है।

#### सबसे तेज 5G डाउनलोडिंग स्पीड वाले देश

यूएई - 654 mbps	कुवैत - 369 mbps
कतर - 516 mbps	मकाऊ - 338 mbps
साउथ कोरिया - 485 mbps	सिंगापुर - 329 mbps
मलेशिया - 451 mbps	सऊदी अरब - 323 mbps
ब्राजील - 449 mbps	न्यूजीलैंड - 316 mbps
डोमिनिकन रिपब्लिक - 403 mbps	बुलगारिया - 306 mbps
बहरीन - 375 mbps	भारत - 301 mbps

#### भारत 5G रोलआउटवाला सबसे तेज देश

भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से 5G रोलआउट करने वाला देश है। भारत में दिसंबर 2023 के आखिरी तक कीहब 400 हजार 5G बेस स्टेशन थे, जिसमें जनवरी 2023 के मुकाबले में 7.7 गुना का इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2023 की चौथी तिमाही में 5G मीडियन डाउनलोडिंग स्पीड 301.86 mbps थी, जो कि 4G स्पीड के मुकाबले में 18 गुना फास्ट है। वहीं 5G अपलोडिंग स्पीड 16.05 mbps दर्ज की गई है, जो कि 4G के मुकाबले 5 गुना फास्ट है।

### OpenAI ने अपने आवाज क्लोन करने वाले टूल को बताया जोखिम भरा, रिलीज रोकती

नई दिल्ली। एजेंसी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी OpenAI ने 2022 में एक वॉइस इंजन तैयार किया था। यह महज 15 सेकंड के रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर किसी की भी आवाज की नकल कर सकता है। अब कंपनी ने कहा है कि इसे आम लोगों के उपलब्ध कराना बेहद जोखिम भरा है। ध्वनि ने कहा कि वह इस पर बातचीत शुरू करना चाहती है और परीक्षणों के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। नीति

#### कई कंपनियों में इस्तेमाल हो रहा है यह फीचर

इस वॉइस इंजन के शुरुआती वर्जन को सबसे पहले फ्लैट्स में टेक्स्ट-टू-स्पीच फीचर के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसकी पूरी क्षमता को कभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया।

#### रणनीति

कंपनी ने अलग-अलग कंपनियों में इसके इस्तेमाल के उदाहरण देते हुए कहा कि इसका उपयोग देखा जा रहा है, लेकिन इसे अभी आम लोगों के लिए रोल आउट नहीं किया जाएगा। बता दें कि OpenAI अभी इसके जरिये व्यक्तिगत आवाज बनाने की अनुमति नहीं देती है।

#### आह्वान

#### कंपनी ने कही जागरूकता बढ़ाने की बात

कंपनी ने इस टूल के रोल आउट से पहले व्यक्तिगत आवाजों की रक्षा करने और लोगों को AI की क्षमताएं और सीमाएं समझाने के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी आह्वान किया है।

कंपनी ने टूल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभी इससे बनाई गई आवाज पर वाटरमार्क होता है, जिससे कंपनियों इसके स्रोत का पता लगा सकती है। साथ ही इससे असली वक्ता की आवाज क्लोन करने से पहले उसकी साफ अनुमति लेनी होती है।

## आपकी EMI घटेगी या बढ़ेगी! RBI MPC की बैठक प्रारंभ, 5 अप्रैल को होगा फैसला

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नए फाइनेंशियल ईयर FY25 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पहली पॉलिसी बैठक बुधवार से शुरू होगी। कमिटी अपना फैसला 5 अप्रैल को सुनाएगी। लगातार छह बार से RBI ves Repo Rate को स्थिर रखा है। इस बार भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि लगातार सातवीं बार भी रेट जस के तस रह सकते हैं। हालांकि, कई अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है इस वित्त वर्ष में आखिर में रेट कट हो सकता है, लेकिन RBI अभी पॉलिसी रेट को यथावत रख सकता है। रीपो रेट वही रेट है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। यह दर फिलहाल 6.5 प्रतिशत है। इस बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अनुमान लगाया है कि RBI की श्रृंखला वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही (Q3FY25) में दरों में कटौती पर विचार कर सकती है। SBI का मानना है कि RBI अपने पॉलिसी स्टैंस को 'return adjustment' के रूप में बनाए रखेगा और पहली रेट



में कटौती Q3FY25 में होगी। हां, रेट कट सायकल काफी उथल हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, RBI Q3FY25 में रीपो रेट में कटौती पर विचार कर सकता है। बैंक ने ऐतिहासिक रुझानों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की तरह विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रेट चेंज के जवाब में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरें दो महीने के अंतराल के साथ बदलती हैं।

#### महंगाई का हाल

SBI रिसर्च रिपोर्ट में ग्रुप की मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने भी कहा था कि RBI फिलहाल अपना रुख नहीं बदलेगा। घोष ने कहा कि ईंधन की मध्यम कीमतों के साथ खाद्य कीमतों के उतार-चढ़ाव की वजह

से महंगाई पर असर पड़ रहा है। खाद्य पदार्थों की बदलती कीमतें घरेलू इन्फ्लेशन को तय करेंगी। वित्त वर्ष 2024 के बाकी महीनों में CPI इन्फ्लेशन 5 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर रहने की उम्मीद है। घोष ने अपने रिपोर्ट में कहा कि पेट्रोल पंपों पर 3.37 फीसदी पर आ गया, जो 52 महीने का निचला स्तर है। इस साल जुलाई तक महंगाई में गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि इसके बाद सितंबर में यह बढ़कर 5.4 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद इसमें गिरावट आएगी। पूरे वित्त वर्ष 2025 के लिए, CPI इन्फ्लेशन औसतन 4.5 प्रतिशत होने की संभावना है।

'विकसित देशों के रुख पर नजर'

RBI की MPC अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कुछ विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों के रुख पर ध्यान दे सकती है। विकसित देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पॉलिसी रेट्स में कटौती की है। वहीं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान ने आठ साल बाद नकारात्मक ब्याज दर की स्थिति को समाप्त किया है। CareEdge Ratings ने अपने पॉलिसी प्रिब्यू में कहा कि RBI की पॉलिसी बेलेंसड होगी और उसका लिक्विडिटी पर फोकस होगा। उनका मानना है कि श्रृंखला वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में दरों में कटौती पर विचार करेगी, क्योंकि हेडलाइन इनफ्लेशन 4% की सीमा के करीब पहुंच जाएगा।

#### 5 अप्रैल को घोषणा

RBI गवर्नर शक्तिकान्त दास की अध्यक्षता वाली MPC की तीन दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू होगी और समीक्षा की घोषणा पांच अप्रैल को की जाएगी। RBI ने पिछली बार फरवरी 2023 में रीपो रेट बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया था।

## भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21 हजार करोड़ रुपए के आंकड़े को पार, जानिए क्या-क्या एक्सपोर्ट कर रहा भारत

एजेंसी

भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बनाया है। साल 2024 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21 हजार करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत में इतना बड़ा आंकड़ा पहली बार देखने को मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि चीन से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हिल गए हैं। साल 2023-24 की तुलना में इस साल डिफेंस एक्सपोर्ट में 32 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

#### किन देशों को भारत हथियार सप्लाई करता है?

भारत दुनिया के 85 देशों को हथियार और दूसरे इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। इसमें इटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फिलिपींस, सऊदी अरब, पोलैंड, इजिप्ट, इजरायल, स्पेन और चिली समेत कई देश हैं।

#### ब्रह्मोस से रॉकेट लॉन्चर तक, 85 देशों को क्या-क्या एक्सपोर्ट कर रहा भारत?

ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारत

ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लेकर आर्टिलरी गन समेत कुछ चुनिंदा चीजें दुनियाभर में एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत हथियारों



से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक दुनिया के लिए 85 देशों को दे रहा है।

#### इसमें शामिल हैं:

- डार्लिनर-228 एयरक्राफ्ट
- राडार
- आर्मर्ड व्हीकल्स
- रॉकेट
- रॉकेट लॉन्चर
- लाइटवेट टॉरपीडो
- आलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम

- फायर कंट्रोल सिस्टम
- नाइट विजन मोनोकुलर एंड बाइकुलर
- हाई प्रीक्वेंसी रेडियो

#### कोस्टल सर्विलंस रडार

#### आगे क्या?

भारत आर्मेनिया को एंटी-एयर सिस्टम एक्सपोर्ट करेगा।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (H) ने डिफेंस सेक्टर में निर्यात के जरिए अगले कुछ सालों में 2500 करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है।

भारत की डिफेंस फर्म कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड 2025 तक आर्मेनिया को आर्टिलरी गन सप्लाई करेगी।

#### भारत कहां तक पहुंचा?

42 फीसदी शेर के साथ वर्तमान में हथियारों के मामले में अमेरिका दुनिया का टॉप एक्सपोर्टर है। वहीं फ्रांस और रूस 11 फीसदी के आंकड़े के साथ दूसरे पायदान पर है। तीसरे पायदान पर चीन है। इसका आंकड़ा 5.8 फीसदी है। भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में इतिहास रचने की तैयारी में है। यही वजह है कि देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आर्म्स एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ रहा है।



### एजेंसी

अमेरिका के बाल्टीमोर में हुए हादसे के बाद छह लोग मिसिंग हैं। इसमें जानमाल का भारी नुकसान हो सकता था लेकिन जहाज में मौजूद भारतीय सेलर्स की तत्परता से कई जानें बच गईं। जहाज के पुल पर टकराने से पहले ही भारतीय सेलर्स ने अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया था। इससे अधिकारियों ने पुल पर ट्रैफिक रोक दिया और बड़ा हादसा होने से टल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने खुद भारतीय सेलर्स की भूमिका की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेलर्स की तत्परता से कई जानें बच गईं। इस घटना ने समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेलर्स की अहम भूमिका को हाइलाइट किया है। जानिए क्या है शिपिंग इंडस्ट्री में भारत की भूमिका...

### भारत की हिस्सेदारी

दुनिया में 90 फीसदी से अधिक गुड्स ट्रेड शिपिंग के जरिए होता है। इस इंडस्ट्री में भारतीय सेलर्स की अहम भूमिका है। दुनिया के कई बड़े जहाज पूरी तरह भारतीय सेलर्स पर निर्भर हैं। शिपिंग इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा सेलर्स देने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। चीन पहले और फिलीपींस दूसरे नंबर पर है। डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ शिपिंग के मुताबिक ग्लोबल सीफेयरर्स में भारत की हिस्सेदारी करीब 10 फीसदी है।

### चार साल में 42% बढ़ोतरी

साल 2013 से 2017 तक इंडियन सेलर्स के लिए शिपबोर्ड जॉब्स में 42.3% तेजी आई। हालांकि भारत अब भी इस मामले में चीन से काफी पीछे है। दुनिया में सेलर्स की कुल संख्या में चीन का करीब 33% है। लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क है। चीन के अधिकांश सेलर्स अपने ही देश के जहाजों पर काम करते हैं जबकि भारत के सेलर्स देसी-विदेशी जहाजों में तैनात हैं। यानी भारतीय सेलर्स ज्यादा ग्लोबल हैं। अगर भारत ज्यादा जहाज बनाएगा और ऑपरेट करेगा तो यह स्थिति बदल सकती है।

# जो बाइडन ने यूं ही नहीं की तारीफ... जानिए शिपिंग इंडस्ट्री का कितना बड़ा खिलाड़ी है भारत

### आंकड़ों का खेल

आंकड़ों के मुताबिक 2013 में भारतीय सेलर्स की संख्या 1,08,446 थी जो 2017 में 1,54,339 पहुंच गई। 2017 में भारतीय मरीन ऑफिसर्स की संख्या 62,016 थी जबकि दूसरे सेलर्स की संख्या 82,734 थी। तबसे यह संख्या काफी बढ़ गई है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारतीय सीफेयरर्स की कुल संख्या 2,50,000 है। इनमें से 1,60,000 प्रोफेशनली सर्टिफाइड सीफेयरर्स हैं जो कार्गो शिप पर काम करते हैं। इसी तरह 90,000 क्रूज लाइनर्स में तैनात हैं।

### भारतीयों की खूबी

भारत लंबे समय से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की वाइट लिस्ट में है। इस लिस्ट में ऐसे देशों को शामिल किया गया है जो एऊ-95 प्दहनहृहर्ह हृ प्दा का पूरी तरह पालन करते हैं। इस लिस्ट में शामिल होने वाले देशों के पास उचित लाइसेंसिंग सिस्टम, ट्रेनिंग सेंटर्स, फ्लेग स्टेट कंट्रोल और पोर्ट स्टेट कंट्रोल की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत के वाइट लिस्ट में होने से दुनियाभर की शिपिंग कंपनियों में भारतीय सेलर्स की काफी डिमांड है।

### कोविड और यूक्रेन वॉर

कोरोना महामारी की शुरुआत में कार्गो शिप में वर्कर्स की कमी हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि शिपिंग कंपनियां भारतीय सीफेयरर्स को हायर करने के लिए आगे नहीं आ रही थीं। ऐसे समय में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अधिकांश देशों से कहा कि वे सीफेयरर्स को अहम वर्कर्स के तौर पर डिजेनेट करें। भारत सरकार ने तुरंत मर्चेंट नेवी के लोगों को इस कैटेगरी में डाल दिया। साथ ही यूक्रेन युद्ध ने भारतीय सीफेयरर्स की डिमांड बढ़ा दी। इस लड़ाई से पहले ग्लोबल सीफेयरर्स में रूस और यूक्रेन की हिस्सेदारी 15% थी। लेकिन लड़ाई के कारण शिपिंग कंपनियों को भारत जैसे देशों का रुख करना पड़ा।

### चुनौतियां

लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती यह है कि मर्चेंट नेवी को प्रतिभावान युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। आजकल अधिकतर युवाओं का रुख आईटी जैसे सेक्टरों को ओर है। दूसरी समस्या यह है कि जहाजों में ट्रेनिंग की पर्याप्त ट्रेनिंग की सुविधा नहीं है। तीसरी समस्या यह है कि इस सेक्टर में महिलाओं की संख्या काफी कम है। अगर इन चुनौतियों से पार पाया जाता है तो जल्दी ही दुनिया के हर पांच सेलर्स में से एक भारतीय होगा।



## क्या है भविष्य

इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि ग्लोबल शिपिंग में भारतीय सीफेयरर्स की संख्या अगले दशक में बढ़कर 20 फीसदी पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए मुख्य रूप से चार फैक्टर जिम्मेदार हैं। भारत में अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। देश में साक्षरता बढ़ रही है। यूरोप में सीफेयरर्स की बड़ी आबादी बूढ़ी हो रही है। इतना ही नहीं भारतीय सेलर्स अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। देश में करीब 166 मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन इनमें करीब 50 फीसदी अकादमिक सीटें खाली हैं। इसलिए इंडियन सीफेयरिंग पूल के विस्तार की काफी संभावनाएं हैं।

## हेल्थ-एनर्जी ड्रिंक के नाम पर फूड प्रॉडक्ट्स बेच रही हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स!

### FSSAI ने किया आगाह

#### नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को चेतावनी दी है कि वे अपनी वेबसाइटों के जरिए हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का दुरुपयोग न करें। FSSAI ने कहा है कि वेबसाइटों के माध्यम से बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित क्लॉसिफिकेशन तय किया जाए और बिस्की बढ़ाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए, जो नियमों के तहत मान्य नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि इएफ ऐक्ट 2006 के मुताबिक हेल्थ ड्रिंक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन देखने में आ रहा है कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी के नाम पर खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं।

प्रॉपराइटरी फूड के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों को डेयरी-आधारित पेय मिश्रण या अनाज-आधारित पेय मिश्रण या माल्ट-आधारित पेय मिश्रण का उत्पादन किया जा सकता है।



आधारित पेय मिश्रण निकटतम श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 'हेल्थ ड्रिंक', 'एनर्जी ड्रिंक' आदि की श्रेणी में बेचा जा रहा है।

FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर 'हेल्थ ड्रिंक' या 'एनर्जी ड्रिंक' की कैटेगरी से ऐसे पेय पदार्थों को हटाकर या डी-लिंक करके इसे तुरंत सुधारें। ग्राहकों तक कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए। FSS ऐक्ट 2006 के प्रावधानों का हर हाल में पालन करना होगा। शब्द 'एनर्जी ड्रिंक' को केवल फूड कैटेगरी सिस्टम (FCS) 14.1.4.1 और 14.1.4.2 (कार्बोनेटेड और गैर-कार्बोनेटेड पानी आधारित स्वादयुक्त पेय) के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादों पर उपयोग करने की अनुमति है।

क्या है प्रॉपराइटरी फूड 'प्रॉपराइटरी फूड' ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन में मानकीकृत नहीं हैं। इसमें कहा गया है, 'इस सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य उत्पादों की प्रकृति और कार्यात्मक गुणों के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाना है, यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता भ्रामक जानकारी का सामना किए बिना अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुन सकें।'

## मल्टीपल मायलोमा के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक प्रभावी उपचार है- डॉ. राहुल भार्गव

### एजेंसी

मार्च मल्टीपल मायलोमा जागरूकता माह है विशेषज्ञों का मानना है कि बीमारी के बारे में जागरूकता और समय पर इलाज से मल्टीपल मायलोमा के प्रभावी उपचार में मदद मिलेगी मायलोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो बोन मैरो हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले स्पंजी ऊतक में शुरू होता है। डॉ. राहुल भार्गव, निदेशक, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम कहते हैं मायलोमा, जिसे मल्टीपल मायलोमा भी कहा जाता है, प्लाज्मा कोशिकाओं का एक कैंसर है, जो विभिन्न जटिलताओं के बावजूद, अभी भी ठीक हो सकता है। इन उपचार विधियों के कारण लोग लंबे समय तक जीवित रहे हैं और

संभवतः 2030 का सूर्योदय देखने को मिलेगा, जिसमें मल्टीपल मायलोमा से पीड़ित सभी रोगियों के लिए इलाज हो सकता है। डॉ. राहुल भार्गव ने आगे कहा ऑटोलॉग्स बीएमटी प्रक्रिया में रोगी से स्वस्थ स्टेम कोशिकाओं को बाहर निकाला जाता है और संरक्षित किया जाता है। फिर शरीर की प्रतिरक्षा को बहाल करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है और फिर व्यक्ति को कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए स्टेम कोशिकाओं को वापस इंजेक्ट किया जाता है। मल्टीपल मायलोमा के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रभावी उपचारों में से एक है। उपचार के दौरान बोन मैरो ट्रांसप्लांट के साथ संयुक्त कीमोथेरेपी मायलोमा वाले लोगों के लिए एक मानक चिकित्सा है। मायलोमा के प्रारंभिक चरण

में हमारे शरीर में कोई लक्षण दिखाई नहीं दे सकते हैं या ये सामान्य रूप से बहुत हल्के हो सकते हैं। मायलोमा हड्डियों में दर्द, विशेष रूप से हमारी पीठ, पसलियों और सर में, कमजोरी, बहुत अधिक प्यास लगने और बार-बार संक्रमण और बुखार का कारण बन सकता है। मायलोमा का निदान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें शुरुआत में कुछ या कोई लक्षण नहीं होते हैं, डॉक्टर यूरिन और हड्डियों में रक्त परीक्षण करने का आदेश देगा, किडनी कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं यह जांचने के लिए रक्त, यूरिया और नाइट्रोजन जैसे कुछ अतिरिक्त परीक्षण और मापने और गिनती के लिए सीबीसी का आदेश देगा। रक्त में कोशिकाएं मायलोमा की पुष्टि करती हैं।



## यूआईडीएआई द्वारा ट्रांज़ैक्शन के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस अपग्रेड करना हुआ अनिवार्य

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत का अग्रणी शाखा रहित बैंकिंग और डिजिटल नेटवर्क, पेनियरबाय अपने सभी रिटेलर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है जिसके अनुसार अब मौजूदा LO फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण डिवाइस को थि डिवाइस में अपग्रेड करना अनिवार्य है। यह अपग्रेड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी हालिया दिशानिर्देशों के अनुपालन में है। निर्देश के अनुसार, सभी मौजूदा LO डिवाइस कुछ महीनों में निष्क्रिय हो जाएंगे। नतीजतन, इस समय सीमा के बाद एईपीएस ट्रांज़ैक्शन LO डिवाइस के माध्यम से संभव नहीं हो

सकेंगे। समय सीमा के बाद, थि डिवाइस इस्तेमाल करने वाले रिटेलर्स अपने एईपीएस व्यवसाय और संभावित आय को जोखिम में डाल सकते हैं।

L1 बायोमेट्रिक डिवाइस एक कॉम्पैक्ट और सुरक्षित समाधान के रूप में कार्य करता है, जो पेनियरबाय ऐप के साथ ब्ल्यूटूथ द्वारा आसानी से जुड़ जाता है। यह डिवाइस यूआईडीएआई के नए नियमों का पालन करता है और एईपीएस ट्रांज़ैक्शन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पेनियरबाय भी अपने रिटेलर्स को इस निर्देश के पालन की सलाह दे रहा है ताकी वे जल्द से जल्द अपग्रेडेड थि डिवाइस खरीदें और एईपीएस सेवाओं में व्यवधान से

बचें। इस विषय पर टिप्पणी करते हुए, पेनियरबाय के सह-संस्थापक, सुभाष कुमार ने कहा, 'आने वाली डेडलाइन को मद्देनजर रखते हुए, रिटेलर्स के लिए तत्काल निर्णय लेना और पेनियरबाय या उनके वितरकों के माध्यम से L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के लिए ऑर्डर देना आवश्यक है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्टॉक की उपलब्धता डेडलाइन के करीब सीमित हो सकती है। इसलिए, रिटेलर्स इन डिवाइस को ऑर्डर करने में देर न करें। हम रिटेलर्स को उनके एईपीएस व्यवसाय की सुरक्षा के लिए इस अवसर का लाभ उठा ग्राहकों को निर्बाध एईपीएस सेवा प्रदान करने के लिए आग्रह करते हैं।'

## भारत की अर्थव्यवस्था बुलेट की रफ्तार से दौड़ेगी, वर्ल्ड बैंक ने जताया भरोसा!

नई दिल्ली। एंजेंसी

वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए खुशखबरी सुनाई है। बैंक ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। यह अनुमान पहले के अनुमान से 1.2 प्रतिशत अधिक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में विकास दर को भी बढ़ाएगी।

**वित्त वर्ष 2025 में भी रहेगी रफ्तार:**

वर्ल्ड बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। बैंक ने कहा है कि भारत में निवेश और खपत में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा, विनिर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र में भी वृद्धि की उम्मीद है।

**दक्षिण एशिया में भी रहेगी चमक:**

वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2024 में दक्षिण एशिया में विकास दर 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान और श्रीलंका में रिकवरी से प्रेरित होगी। यह अनुमान भारत के लिए एक अच्छी खबर है। यह दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में बढ़ रही है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह केवल एक अनुमान है। वास्तविक विकास दर इससे अधिक या कम हो सकती है।

## एचपी ने पेश किया एआई से लैस ओमेन ट्रांसेंड 14

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एचपी ने भारत में अपनी एआई-एनहॉन्स्ड ओमेन ट्रांसेंड 14 लैपटॉप सीरीज़ पेश करने का एलान किया। गेम खेलने और कंटेंट क्रिएट करने जैसे दोनों क्षेत्रों में रुचि रखने वाले गेमर्स के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ओमेन ट्रांसेंड 14 लैपटॉप में एनवीडिया जीईफोर्स आरटीएक्स 4060 ग्राफिक्स दिया गया है जो बेहतरीन गेमप्ले एक्सपीरियंस और ग्राफिक्स के लिए एआई फीचर्स उपलब्ध कराता है। नए ओमेन में प्रयोग किए गए इंटर कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स की मदद से गेमर्स लैटेन्सी गेम्स से जुड़ने या बहुत कम्यूट-इंटेसिव टास्क करने में सुगमता का अनुभव करेंगे। ओमेन ट्रांसेंड 14 में इंटर कोर एनवीडिया के माध्यम से लोकल एआई क्षमता के साथ-साथ ओटर डॉट एआई के साथ बिल्ट-इन एआई सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे मीटिंग या क्लास के

दौरान लाइव ट्रांसक्रिप्ट एवं रियल-टाइम कैप्शन, ऑडियो ट्रांस्क्राइब के लिए रिपोर्ट फंक्शन और एआई-जनरेटेड नोट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। एचपी इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं मैनेजिंग डायरेक्टर इप्सिता वासगुप्ता ने कहा एचपी में हमारा मिशन एआई की ताकत का इस्तेमाल करते हुए यूसर्स को सशक्त करना तथा उनके वर्किंग, लिविंग और गेमिंग एक्सपीरियंस को रिडिफाइन करना है। हमें एआई-एनहॉन्स्ड पीसी के मामले में इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो पेश करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। एआई आधारित पर्सनलाइजेशन वेब माध्यम से हम ज्यादा पर्सनलाइज़्ड एवं मीनिंगफुल यूसजर एक्सपीरियंस तैयार कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ उनके इंटरैक्ट करने के तरीके को क्रांतिकारी तरीके से बदल रहे हैं।

ओमेन ट्रांसेंड 14 की बेहतरीन

परफॉर्मेंस में मदद के लिए इसमें इंटर कोर के साथ मिलकर तैयार किया गया नया कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम के तहत इसका चेसिस हवा को अंदर खींचता है और एक वैपर चेंबर का प्रयोग करते हुए प्रेशर जोन बनाता है, जिससे रियर वेंट के माध्यम से गर्म हवा बाहर निकल जाती है। इस सिस्टम ने इसे दुनिया का सबसे कूल 14 इंच गेमिंग लैपटॉप बना दिया है। स्ट्रीमिंग और गेमर्स इसमें लगे एनपीयू का लाभ लेते हुए 24.6 फ्रेम पर सेकेंड (एफपीएस) की इम्प्रूवमेंट के साथ स्ट्रीमिंग और गेमप्ले को ज्यादा सुगम बना सकते हैं। नया पावरफुल ओमेन ट्रांसेंड 14 एचपी का सबसे हल्का गेमिंग लैपटॉप भी है। इसमें बेहतर थर्मल एवं नॉइस प्रेशरन तथा क्रिएशन को आसान बनाने के लिए ओमेन टेम्पेस्ट कूलिंग जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

एचपी ने ओमेन ट्रांसेंड 14

को ऐसे गेमर्स के लिए बेहतरीन साथी के रूप में डिजाइन किया है, जो कंटेंट क्रिएटर भी हैं। इसके पोर्टेबल डिजाइन और मजबूत फीचर्स के साथ यूसजर बहुत आसानी से खुद को गेमिंग एडवेंचर का हिस्सा बना सकेंगे और सुगमता से अपनी क्रिएटिविटी को सबसे सामने ला सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग गेमप्ले सेशन से लेकर वीडियो एडिटिंग एवं डिजिटल कंटेंट डिजाइनिंग तक ओमेन ट्रांसेंड 14 यूसर्स को किसी भी तरह का समझौता किए बिना गेमिंग और क्रिएशन की नई ऊंचाइयां छूने में सक्षम बनाता है।

इसका कीबोर्ड लैटिस-लेस डिजाइन में है, जिससे एज-टु-एज कीकंप मिलता है। हालांकि मैकेनिकल कीबोर्ड के लिए कीकैप को हाइपरएक्स के पडिंग कैप के ऊपर मॉडल किया गया है, जिससे हर शकीश का बॉर्डर चमकदार हो जाता है।

## एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर एसएफबी का विलय

1 अप्रैलसे प्रभावी, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बीच पूरा हुआ पहला मर्जर एंड एक्विजिशन मुंबई आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मार्च, 2024 को जारी निर्देशों के अनुसार, भारत के सबसे बड़े एसएफबी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक (फिनकेयर एसएफबी) के एयू एसएफबी में विलय (एकीकरण) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी है। यह विलय एयू एसएफबी को मजबूत भौगोलिक उपस्थिति, अलग अलग सेगमेंट के ग्राहकों और व्यापक उत्पाद पेशकश का लाभ उठाकर एक मजबूत अखिल भारतीय रिटेल बैंकिंग फ्रंचाइजी स्थापित करने में मदद करता है।

ऑल-स्टॉक मर्जर डील में 29 अक्टूबर, 2023 को की गई घोषणा के तहत, फिनकेयर एसएफबी के शेयरधारकों को विलय के फायदे का भोग कराने के लिए एयू एसएफबी में 579 इक्विटी शेयर हासिल होंगे। इस विलय को 4 मार्च, 2024 को आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिली थी और यह 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हो गया है। विलय को पहले 23 जनवरी, 2024 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के प्रावधानों के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा मंजूर किया गया था।

यह भारत के विलय और अधिग्रहण (मर्जर एंड एक्विजिशन - एमएंडए) क्षेत्र में किसी विलय को सबसे तेज मिलने वाली मंजूरी में से एक है जिसमें सभी अप्रैल 4.5 महीने की अवधि में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ, एयू एसएफबी 1 करोड़ से अधिक के संयुक्त ग्राहक आधार, 43,500 से अधिक कर्मचारियों और 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,35,000 भौतिक टचपॉइंट के नेटवर्क के साथ एक मजबूत यूनियट बन गया है, जिसका डिपॉजिट बेस 89,854 करोड़ रुपये और बिलेंस शीट का आकार 1,16,695 करोड़ रुपये है। अब बैंक का फोकस अगले 9-12 महीनों के भीतर एक सहज और निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने और ग्राहकों को असाधारण बैंकिंग सेवाएं और वैल्यू प्रदान करने पर केंद्रित हो गया है।



## युवा स्टेशनरी ने 'ओगी एंड द कॉकरोचेज़' के लिए लाइसेंसिंग अधिकार प्राप्त किए

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

हाउस ऑफ नवनीत एजुकेशन से युवा को अग्रणी एनिमेटेड सीरीज़ - ओगी एंड द कॉकरोचेज़ के साथ अपने सहयोग की घोषणा करते हुए बेहद खुशी है। Sony YAY! ने XilamAnimation से लाइसेंस प्राप्त, एनिमेटेड कॉमेडी ने अपनी मनोरंजक और गुदगुदाने वाली कहानियों के साथ कई वर्षों में दुनिया भर के दर्शकों के दिलों पर घर कर लिया है। ओगी, आकर्षक नीली बिल्ली, एक आइकन बन गई है, जिसने दुनिया भर के दर्शकों का दिल

जीत लिया है। उसकी अपील सीमाओं और भाषाओं को पार करती है, सभी उम्र के दर्शकों के साथ जुड़ती है। बच्चे ओगी के प्यारे स्वभाव और जुड़ सकने वाले अनुभवों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे वह दोस्ती की दुनिया में सबसे चाहा जाने वाला चरित्र बन जाता है। इसकी सफलता सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है; ओगी एक साथी बन गया है, एक दोस्त जिसे बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने साथ रखना चाहते हैं। युवा ने Sony YAY! से 'ओगी एंड द कॉकरोचेज़' के लिए लाइसेंसिंग अधिकार प्राप्त

किए हैं। यह सहयोग स्टेशनरी उत्पादों की एक विविध श्रेणी में विस्तारित होगा, जिसमें जंबो-आकार और नियमित नोटबुक, कॉलरिंग और एक्टिविटी बुक, कैंबो क्विज और परीक्षा बोर्ड शामिल हैं।

Youva और 'ओगी एंड द कॉकरोचेज़' के बीच इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य स्टेशनरी की दुनिया में खुशी और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, प्रशंसकों और उपभोक्ताओं को उनके पसंदीदा एनिमेटेड पात्रों की विशेषता वाले उत्पादों की एक रोमांचक सीरीज़ प्रदान करना है। युवा के मुख्य

रणनीति अधिकारी अभिजीत सान्याल ने कहा, 'हम 'ओगी एंड द कॉकरोचेज़' के साथ मिलकर खुश हैं, एक ऐसा शो, जो दुनिया भर के दर्शकों की कल्पना में शामिल हो चुका है।' यह सहयोग अद्वितीय और आकर्षक उत्पादों के माध्यम से हमारे ग्राहकों के लिए नयापन और खुशी लाने का हमारा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम एक सफल साझेदारी की आशा करते हैं जो निरसंदेह स्टेशनरी के प्रति उत्साही और प्रिय एनिमेटेड सीरीज़ के प्रशंसकों पर एक स्थायी छाप छोड़ेगी।

# डॉ. रेड्डीज ने भारत में सनोफी ने वैक्सीन ब्रांड्स के लिए विशेष वितरण साझेदारी की

## इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

वैश्विक फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड (बीएसई: 500124, एनएसई: डीआरएडी, एनवाईएसई: डीआरडी) और आईपीटी नेटवर्क, एनएसई: आईपीटी, एनएसई: आईपीटी, एनएसई: आईपीटी, यहाँ से इसे 'डॉ. रेड्डीज' कहा जाएगा), ने भारत में निजी बाजारों में सनोफी हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('SHIPL') के वैक्सीन ब्रांड्स के प्रमोशन और वितरण के लिए इसके साथ एक विशेष साझेदारी करने की घोषणा की। इस समझौते के अंतर्गत डॉ. रेड्डीज को सनोफी के स्थापित और विश्वसनीय पीडियाट्रिक एवं एडल्ट वैक्सीन ब्रांड्स हेक्सीक्सिमर, पेंटाक्सिमर, टेट्राक्सिमर, मेनैक्टार, फ्लूक्वाइड, एडासेलर और



अवेक्सिमर 80यू के प्रमोशन और वितरण के विशेष अधिकार मिल गए हैं। IQVIA MAT फरवरी 2024 के अनुसार इन ब्रांड्स ने मिलकर लगभग 426 करोड़ रुपये (लगभग USD 51 मिलियन) की बिक्री दर्ज की है। सनोफी देश में इन ब्रांड्स का स्वामित्व, निर्माण एवं आयात करना जारी रखेगी।

सनोफी में वैक्सिस के लिए

जनरल मैनेजर इंडिया, प्रीति फुटनानी ने कहा, 'भारत में पिछले कुछ सालों में वैक्सिस पर विश्वास शिखर पर पहुँच गया है। लेकिन फिर भी देश में वैक्सिस से बचे हुए बड़े जन समूह के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत में अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को पूरा करने और अपनी भौगोलिक पहुँच का विस्तार करने के लिए हमें विशेष वितरण और

प्रमोशन के लिए डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (डॉ. रेड्डीज) के साथ साझेदारी करने की खुशी है। हमें विश्वास है कि इस साझेदारी द्वारा वैक्सिस के बेहतर कवरेज के साथ लाखों लोगों को वैक्सिस द्वारा रोगी जा सकने वाली बीमारियों से बचाने का हमारा वादा पूरा करने में मदद मिलेगी।'

एम.वी. रमना, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, ब्रांडेड मार्केट्स (भारत एवं उभरते बाजार), डॉ. रेड्डीज ने कहा: 'हमें भारत में हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के साथ अपनी संलग्नता का विस्तार करने और सनोफी के स्थापित एवं विश्वसनीय वैक्सिस ब्रांड्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रमोशन एवं वितरण की अपनी शक्ति का उपयोग करने का अवसर मिलने की खुशी है।'

# विक्स का भारत के लिए इनोवेशन लगातार जारी

## इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाला कफ एवं कोल्ड ब्रांड, विक्स राहत प्रदान करने और देखभाल की अपनी 125 सालों से ज्यादा लंबी विरासत के साथ बेहतर उत्पाद प्रदान करने के लिए लगातार इनोवेट कर रहा है, ताकि उनकी मदद से परिवार और दोस्त एक दूसरे का खयाल रख सकें। आज इस ब्रांड ने सिरदर्द से जल्द राहत के लिए नया विक्स रोल-ऑन पेश किया, जो सिरदर्द से तुरंत राहत प्रदान करता है। यह नींद न आने की समस्या के लिए विक्स ZzzQuil Natura (दुनिया के #1 स्लीप एड ब्रांड की ओर से) और विश्व

में इसके पहले स्टीम इनहेलेशन कैंपूल, न्यू विक्स वेपोरब स्टीम पॉइंस, के लॉन्च के बाद भारत में पिछले 12 महीनों में विक्स का तीसरा इनोवेशन है। पी एंड जी इंडिया के कैटेगरी लीडर, कंज्यूमर हेल्थकेयर, साहिल सेठी ने कहा, 'विक्स कई पीढ़ियों से भारतीयों को सर्दी, खाँसी और फ्लू के लक्षणों से आराम दिलाता आया है। हम अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को सुनकर उनके अनुरूप अपने उत्पादों का निर्माण और पैकेजिंग करके इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें सर्दी और खाँसी के साथ होने वाले सिरदर्द से तुरंत राहत देने के लिए अपना नया विक्स रोल-ऑन पेश करने

पर गर्व है। सिरदर्द लोगों को कभी भी हो सकता है, जिससे उन्हें बेचैनी होती है और उनकी काम करने की क्षमता प्रभावित होती है।

डॉ. जसप्रीत कोचर, डायरेक्टर, विक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने कहा, 'नया विक्स रोल-ऑन एक बेहतरीन फॉर्मूला है, जो पुदीना (मेंथल) और कर्पूर (कपूर) जैसे आयुर्वेदिक तत्वों की शक्ति के साथ भारतीयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह अचानक शुरू होने वाले सिरदर्द से तुरंत, प्रभावशाली और ऑन-द-गो राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि सिरदर्द से आपका दैनिक कामकाज प्रभावित ना हो।

# सैमसंग ने अपने और फ्लैगशिप डिवाइसेज पर गैलेक्सी एआई का विस्तार किया

## मोबाइल एआई का अनुभव सब तक पहुंचाने की कोशिश

### इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड, सैमसंग ने आज मोबाइल एआई को सभी तक पहुंचाने की अपनी कोशिश के तहत गैलेक्सी की और प्रमुख डिवाइसेस पर गैलेक्सी एआई फीचर्स लाने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत आज से होगी और यह गैलेक्सी S23 सीरीज, S23 FE, Z फोल्ड5, Z फिलप5 और टैब S9 सीरीज में उपलब्ध होगा। हाल ही में लॉन्च की गई गैलेक्सी S24 सीरीज के मुताबिक यह अपडेट यूजर्स के मोबाइल एआई अनुभव को और बेहतर बनाता है।

गैलेक्सी एआई फीचर्स के उपलब्ध होने से अब गैलेक्सी S23 सीरीज, S23 FE, Z फोल्ड5,



Z फिलप5 और टैब S9 सीरीज के यूजर अब सर्कल टू सर्च, लाइव ट्रांसलेट और नोट असिस्ट समेत कई फीचर्स का लाभ उठा सकेंगे। गैलेक्सी इकोसिस्टम में गैलेक्सी एआई का व्यापक एकीकरण एआई-

समर्थित मॉडल पर रोजाना के काम को सहज और आसान बना देता है, जिससे दक्षता बढ़ती है। जब आप अपने डिस्क्रेट पर किसी इमेज पर सर्कल या गोला बनाते हैं या उसे हाइलाइट करते हैं या टैप करते हैं तो गूगल के साथ सर्कल टू सर्च सूचनापरक, उच्च गुणवत्ता वाले गूगल सर्च रिजल्ट को सामने लाता है। लाइव ट्रांसलेट फीचर फोन कॉल के दौरान दो-तरफा व रियल टाइम में वापस और टेक्स्ट अनुवाद करता है, जिससे यात्रा के दौरान आरक्षण बुक करना या अपने दादा-दादी के साथ उनकी भाषा में बात करना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाता है।

# इवास इलेक्ट्रिकल्स ने पेश किया एनर्जी-एफिशिएंट मैग्नेस बीएलडीसी फैन कलेक्शन

## भारत का पहला पीओएस टेक्नोलॉजी आधारित बीएलडीसी फैन

### इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की लीडिंग कंस्ट्रक्शन मैटेरियल कंपनी इफ्रा.मार्केट द्वारा संचालित इवास इलेक्ट्रिकल्स ने अपना लेटेस्ट इनोवेशन - मैग्नेस बीएलडीसी फैन रेंज लॉन्च किया है। यह अत्याधुनिक सीरीज भारत में पहली बार फोटॉन ऑब् बीव (पीओएस) तकनीक पेश करती है, जो सीलिंग फंखों में एक नया मानक स्थापित करती है। बेहतरीन

एयर-डिलिवरी की क्षमता और एनर्जी की बचत करने वाली 32 ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (BLDC) मोटर डिजाइन के साथ, मैग्नेस आपके घर के अनुभव को बदल देता है। मैग्नेस बीएलडीसी फैन कलेक्शन (फंखों का कलेक्शन) घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में इनोवेशन और स्थिरता के प्रति इवास इलेक्ट्रिकल्स की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। फर्स्ट-इन-इंडिया

पीओएस टेक्नोलॉजी प्रशंसकों के लिए दिखने में बेहतर और एक चौकाने वाला प्रोडक्ट पेश करती है, जबकि बीएलडीसी टेक्नोलॉजी ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता देती है और हवा के प्रवाह को बढ़ाती है। दिखने में खूबसूरत लगे, इस बात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया, मैग्नेस बीएलडीसी फैन कलेक्शन किसी भी कमरे में स्मार्ट टच देता है, जिससे एक संपूर्ण

अनुभव बनाता है।

इस अवसर पर इवास इलेक्ट्रिकल्स के प्रेसिडेंट, रोहित माथुर ने कहा कि यह इनोवेशन के प्रति हमारे समर्पण का एक सच्चा उदाहरण है। हम मैग्नेस सीरीज पेश करते हुए रोमांचित हैं। पीओएस टेक्नोलॉजी का एकीकरण सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्राहकों को कूलिंग समाधान से भी कुछ अधिक



प्रदान करने की हमारी सोच का प्रमाण है। अपनी तकनीकी क्षमता, शानदार डिजाइन और कॉस्ट-एफिशिएंट (लागत-कुशल)

सुविधाओं के साथ, यह रेंज पर्यावरण के लिहाज से भी ठीकाऊ है, जो हमारे ग्राहकों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करती है।